ई-संदेश

16 अक्टूबर, 2025 | अंक 175

सात दिन - सात पृष्ठ

दीपावली पर महिलाओं को मिला प्रधानमंती उज्ज्वला योजना के निःशुल्क गैस सिलेण्डर का उपहार। प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को रिफिल सब्सिडी हस्तान्तरित की गई।

› खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उसेआत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने की क्षमता रखती हैं : मुख्यमंत्री

› समाज की जागरूकता विकास लेकर आती है और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाती है : मुख्यमंत्री

› एक करोड़ रु0 से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं : मुख्यमंत्री

› सरकार का अभियान है कि प्रदेश के सभी वर्ग के व्यक्तियों को उनकी जरूरत के अनुसार मकान प्राप्त हो : मुख्यमंत्री

› गोमती केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और जीवनधारा की प्रतीक : मुख्यमंत्री

› विंध्य और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हर घर में 15 दिसंबर, 2025 तक नल से शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए : मुख्यमंत्री

› प्रतिस्पर्धा ही विकास को प्रोत्साहित करती है, खेलकूद प्रतियोगिताएं इसमें सहयोगी बनती हैं : मुख्यमंत्री

› सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से वंचित न रहे: मुख्यमंत्री

› प्रदेश के नगरों के तीव्र गति से बदलते विकास स्वरूप को देखते हुए अब एक व्यापक 'शहरी पुनर्विकास नीति' की आवश्यकता : मुख्यमंत्री

› कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

› प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल सब्सिडी हस्तान्तरित की : मुख्यमंत्री

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उसे आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने की क्षमता रखती हैं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 09 अक्टूबर, 2025 को विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 36वें क्षेत्रीय खेलकूद के समापन समारोह विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षण संस्थान से जुड़े खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उसे आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने की क्षमता रखती हैं। वर्तमान समय में खेल प्रतिस्पर्धाएं सर्वांगपूर्ण जीवन पद्धति बन चुकी हैं। जब खिलाड़ी हार-जीत की परवाह किये बिना आगे बढ़ता है, तो विजयश्री उसके चरणों को स्वयं ही चूमती है। उन्होंने समारोह में प्रदेश सरकार द्वारा भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, झांसी के प्रांगण में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की घोषणा की , जिससे यहां के विद्यार्थियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में देश में खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक अभियान चलाये गये हैं। इनमें खेलो इण्डिया, फिट इण्डिया मूवमेण्ट, प्रत्येक जनपद में खेलो इण्डिया सेण्टर्स की स्थापना आदि प्रयास सम्मिलित हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक गांव में खेल का मैदान, विकास खण्ड में मिनी स्टेडियम, जनपद में स्टेडियम तथा नगर निकाय में ओपन जिम का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विगत 03 वर्षों में राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले 500 से अधिक खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां प्रदान की है। इसमें डिप्टी एस0पी0, खेल अधिकारी, कानूनगो, तहसीलदार जैसे पद सम्मिलित हैं। ओलम्पिक गेम्स (एकल वर्ग) में स्वर्ण पदक पर 06 करोड़ रुपये, रजत पदक पर 04 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 02 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। ओलम्पिक गेम्स (टीम गेम्स) में स्वर्ण पदक पर 03 करोड़ रुपये, रजत पदक पर 02 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 01 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 03 करोड़ रुपये, रजत पदक पर 1.50 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।

कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.50 करोड़ रुपये, रजत पदक पर 75 लाख रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। विश्वकप में स्वर्ण पदक पर 1.50 करोड़ रुपये, रजत पदक पर 75 लाख रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 50 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। सैफ गेम्स एवं नेशनल गेम्स (एकल वर्ग) में स्वर्ण पदक पर 06 लाख रुपये, रजत पदक पर 04 लाख रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 02 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। सैफ गेम्स एवं नेशनल गेम्स (टीम गेम्स) में स्वर्ण पदक पर 02 लाख रुपये, रजत पदक पर 01 लाख रुपये तथा कांस्य पदक जीतने पर 50 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओलम्पिक गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रतिभाग किए जाने पर प्रोत्साहन स्वरुप 10-10 लाख रुपये तथा कॉमनवेल्थ गेम्स एवं एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 05-05 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किये जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार, एशिया कप, एशियन सीनियर चैम्पियनशिप, यूथ ओलम्पिक गेम्स, यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स, जूनियर विश्वकप, जूनियर विश्व कप/एशियन चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर, जूनियर, सब-जूनियर, मिनी/यूथ/कैडेट पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार-पुरुष वर्ग में 'लक्ष्मण पुरस्कार' एवं महिला वर्ग में 'रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचन्द पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल के क्षेत्र में पद्मश्री व पद्मभूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को 20,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 4,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 6,000 रुपये तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देशवासियों के समक्ष विकसित भारत का संकल्प रखा है। प्रत्येक भारतवासी को विकसित भारत की संकल्पना में अपना योगदान देना चाहिए।

समाज की जागरूकता विकास लेकर आती है और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाती है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 09 अक्टूबर, 2025 को जनपद जालौन में लगभग 1,900 करोड़ रुपये लागत की 305 विकास परियाजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। ये विकास परियोजनाएं पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, निराश्रित गोवंश, सिंचाई व अन्य विकास कार्यां से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाभी, प्रमाण-पत्र, प्रतीकात्मक चेक, स्वीकृति-पत्र, प्रशस्ति-पत्र प्रदान किये और बच्चों को अन्नप्राशन कराया।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उहोने सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समाज की जागरूकता विकास लेकर आती है और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाती है। लोगों की समस्याओं का निराकरण मेरिट के आधार पर किया जाए। किसी गरीब, दलित, वंचित, व्यापारी, किसान, महिला व समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ शोषण व अत्याचार करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार कठोर कार्यवाही करेगी। हमें जातिवादी मानसिकता से अपने आप को बचाना होगा। सरकार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है। विकास की शत प्रतिशत धनराशि विकास में ही खर्च हो, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। यही स्वसंकल्प हमें विकसित भारत की ओर लेकर जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने दीपावली के उपहार स्वरूप जालौनवासियों को आज लगभग 1,900 करोड़ रुपये की विकास परियाजनाओं की सौगात दी है। जनपद जालौन में पांच नदियां यमुना, चम्बल, सिंध, पहूज तथा क्वारी एक साथ मिलती हैं। यह स्थान पचनदा के रूप में जाना जाता है, जो यहां के आध्यात्मिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि पचनदा का प्रोजेक्ट बनाकर जनपद जालौन की भूमि को एक बार फिर सबसे उर्वरा भूमि के रूप में बदलने का कार्य किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कालपी के हस्तशिल्पियों ने हैण्डमेड कागज के माध्यम से जनपद जालौन को एक नयी पहचान दिलाई है। राज्य सरकार ने हैण्डमेड कागज को 'एक जिला एक उत्पाद' बनाकर इसे अलग पहचान देने का कार्य किया है। जालौनवासियों ने सम-विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए विकास को प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि आज लगभग 1,900 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश विकसित तभी होगा, जब जालौन विकसित होगा। जालौन को विकसित बनाने के लिए हमें ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायत, सभी वार्ड व नगर निकायों को आत्मनिर्भर व विकसित बनाना होगा। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 28 घण्टे तक चर्चा की गयी थी। प्रदेश सरकार ने विकसित उत्तर प्रदेश/2047 के विजन डॉक्यूमेण्ट में आम नागरिकों की सहभागिता के लिए 'विकसित उत्तर प्रदेश समर्थ उत्तर प्रदेश/2047 सुझाव पोर्टल' व क्यू0आर0 कोड की व्यवस्था दी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जी0एस0टी0 रिफॉर्म के माध्यम से आम नागरिकों को महंगाई से राहत दी गयी है। डबल इंजन सरकार समाज के हर वर्ग के लिए बिना भेदभाव शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रदेश में 60 लाख गरीबों के पक्के मकान बन गये हैं। 02 करोड़ 61 लाख गरीबों के घरों में शौचालय, 01 करोड़ 86 लाख गरीबों को निःशुल्क रसोईगैस कनेक्शन व 01 करोड़ 56 लाख लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश सरकार ने साढ़े 08 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का कार्य किया है। एम0एस0एम0ई0 के माध्यम से 02 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बड़े निवेश के माध्यम से 60 लाख नौजवानों को नौकरी व रोजगार की गारण्टी मिली है।

एक करोड़ रु0 से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 09 अक्टूबर, 2025 को जनपद झाँसी में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी ने बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी बनाने हेतु विक्रय विलेख प्रबन्धन प्रणाली का शुभारम्भ भी किया।समीक्षा बैठक से पूर्व 04 हजार लोगों की क्षमता वाले आधुनिक एक्जिबिशन सेण्टर का लोकार्पण किया, जिसमें प्रदर्शनियां, विवाह, इन्वेस्टर मीट जैसे विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे एक्जिबिशन सेण्टर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को चेक प्रदान किए तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लाभार्थियों को टूलकिट वितरित किए।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 01 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। नोडल अधिकारी नियमित रूप से कार्य का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ कार्य को पूर्ण कराएं। जिलाधिकारी, नोडल अधिकारी के साथ कार्य के सम्बन्ध में नियमित बैठक करे। मुख्यमंत्री जी ने अतिवृष्टि से किसानों की फसल नुकसान की भरपाई हेतु कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अनुदान राशि तत्काल संबंधित किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, गोबर से बने पेंट से जनपद के सभी सरकारी भवनों की पेंटिंग कराए जाने और प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि तुलसी उत्पादन के लिए जनपद के किसानों को प्रोत्साहित किया जाए तथा तुलसी उत्पादन को स्थानीय औषधि निर्माता फर्म से जोड़ा जाए ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी बनाने हेतु विक्रय विलेख प्रबन्धन प्रणाली का शुभारम्भ किया गया है। इस प्रणाली से भूमि अधिग्रहण में जहां एक ओर पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर कास्तकार/किसान को किया गया भुगतान उनके बैंक खाते में अंतरित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन उद्यमियों को भूमि आवंटित की जाए, उन्हें 03 वर्षों में निवेश प्रारम्भ करना होगा। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि क्षेत्र के युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए ताकि क्षेत्र में जो औद्योगिक इकाई स्थापित हो, वहां उन्हें नौकरी मिल सके। यह कार्य बेहतर नियोजन के तहत किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद में माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत महिलाओं और बालिकाओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके लिए पुलिस पेट्रोलिंग को तेज किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने जनपद झांसी को टी0बी0 मुक्त बनाए जाने के अभियान में जनप्रतिनिधियों को शामिल करते हुए अधिक से अधिक टी0बी0 मरीजों को गोद लेने और उनसे लगातार संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद की लगभग 20 लाख की आबादी है, हमें यह प्रयास करना होगा कि इस वर्ष के अंत तक जनपद को टी0बी0 मुक्त बनाया जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय को सक्रिय किया जाए, ताकि गांव के व्यक्तियों को अपनी समस्याओं के लिए भटकना न पड़े। ग्राम सचिवालय में ही उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रमाण-पत्र उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मण्डियों को बेहतर ढंग से संचालित किए जाने के निर्देश दिए।

सरकार का अभियान है कि प्रदेश के सभी वर्ग के व्यक्तियों को उनकी जरूरत के अनुसार मकान प्राप्त हो : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 10 अक्टूबर, 2025 को जनपद गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत 160 ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 फ्लैट्स के आवंटियों को चाभी का वितरण किया। उन्होंने 118 करोड़ रुपये लागत की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार का यह अभियान है कि प्रदेश के सभी वर्ग के व्यक्तियों को उनकी जरूरत के अनुसार मकान प्राप्त हो। इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित कर रही है। प्रदेश के सभी गरीब, स्ट्रीट वेण्डर, श्रमिकों के साथ मध्यम वर्ग के लोग जैसे डॉक्टर, पत्रकार, व्यापारी आदि के लिए भी आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके लिए सरकार कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की यह आकांक्षा होती है कि वह अपने जीवन में स्वयं के सामर्थ्य से अपना एक घर बना पाए। आज यहां दीपावली के पूर्व पवित्र कार्तिक माह में 160 परिवारों की यह आकांक्षा पूर्ण हुई है। 80 परिवारों को ई0डब्ल्यू0एस0 तथा 80 परिवार को एल0आई0जी0 फ्लैट्स प्राप्त हुए हैं। इस आवंटन में किसी भी प्रकार की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी है। आज 160 गरीब परिवारों अर्थात लगभग 600 से 700 लोगों को एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज उनके जीवन का एक बड़ा सपना पूरा हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पाम पैराडाइज आवासीय योजना में 40 विस्थापित परिवारों को आवास प्राप्त हुआ है। 120 अन्य परिवारां को लॉटरी के माध्यम से आवास की सुविधा प्राप्त हुई है। लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण एवं अन्य सम्बन्धित विभाग ने मिलकर आवासों का निर्माण किया है। आगे भी विभिन्न आवासीय योजनाओं के माध्यम से अन्य लोगों को आवास प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। आज यहां गोरखपुर में 118 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्य हुआ है, जो गोरखपुर के विकास को गति प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस आवासीय परियोजना में ई0डब्ल्यू0एस0 फ्लैट 35 वर्ग मीटर में बनाए गए और इसकी कीमत 5.40 लाख रुपये है। बाजार में इसकी कीमत 12-13 लाख रुपये है, किन्तु प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी देकर गरीब वर्ग के लोगों को 5.40 लाख में आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार एल0आई0जी0 फ्लैट की लागत 19-20 लाख रुपये है, किन्तु सरकार इसे 10.80 लाख रुपये में उपलब्ध करा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों में देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 04 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराये गए हैं। प्रदेश में भी इस दौरान लगभग 60 लाख गरीबों को निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक अच्छी सरकार में विकास भी होता है और गरीबों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। आज इसी क्रम में गोरखपुर में लाभार्थियों को फ्लैट आवंटन का कार्य किया जा रहा है, जिन लोगों को इस सोसाइटी में आवास की सुविधा प्राप्त हुई है। वह यह प्रयास करें कि यह एक अच्छी सोसाइटी बने। सभी लोग सद्भाव के साथ यहां रहें। सभी लोग मिलकर एक समिति भी गठित कर सकते हैं और उस समिति में कुछ आर्थिक योगदान कर उसके माध्यम से हाउसिंग सोसाइटी के मेनटेनेन्स का कार्य भी कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं, तो सोसाइटी में लम्बे समय तक आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

गोमती केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और जीवनधारा की प्रतीक : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 12 अक्टूबर, 2025 को यहां लखनऊ में टेरिटोरियल आर्मी के साथ गोमती तट की स्वच्छता के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री जी ने 'स्वच्छ, अविरल और निर्मल गोम ती' के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए 'गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन' की घोषणा की। मिशन की विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक परियोजना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता से चलने वाली एक जन-आंदोलनात्मक पहल होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पीलीभीत से गाजीपुर तक प्रवाहित गोमती केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक विरासत और जीवनधारा की प्रतीक है। गोमती का पुनर्जीवन केवल जल शुद्धिकरण का नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और पर्यावरण के पुनर्संवर्धन का व्यापक अभियान है। यह मिशन पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी साझा प्रतिज्ञा का प्रतीक बनेगा।गोमती में एक बूंद सीवरेज न गिरे, इसके लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नदी किनारे बसी अवैध बस्तियों में घुसपैठियों की पहचान कर विधिसम्मत कार्यवाही की जाए, ताकि गोमती के तटों पर स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मिशन का दायरा पीलीभीत से गाजीपुर तक गोमती नदी के सम्पूर्ण प्रवाह क्षेत्र को कवर करेगा, जिससे गोमती अपने पूरे विस्तार में स्वच्छ, अविरल और निर्मल रुप पुनः प्राप्त कर सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह मिशन केवल प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नदी के जैविक, सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक पुनर्जीवन का माध्यम बनेगा। कार्ययोजना के अन्तर्गत लखनऊ में इकाना वेटलैंड और साजन झील जैसे नए वेटलैंड विकसित किए जाएंगे। नदी किनारे के अवैध अतिक्रमणों को हटाने, घाटों के सौंदर्यीकरण, और तटीय हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबन्ध लागू किया जाएगा, क्योंकि सीवर सिस्टम को चोक करने और प्रदूषण बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका है।

मुख्यमंत्री जी ने मिशन के अन्तर्गत नगरीय सीवेज का 95 प्रतिशत से अधिक अवरोधन, नदी प्रदूषण को न्यूनतम स्तर तक लाना और नदी तटीय पारिस्थितिकी के पुनरुद्धार का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि यह मिशन केवल प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नदी के जैविक, सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक पुनर्जीवन का माध्यम बनेगा।

कार्ययोजना के अन्तर्गत लखनऊ में इकाना वेटलैंड और साजन झील जैसे नए वेटलैंड विकसित किए जाएंगे। नदी किनारे के अवैध अतिक्रमणों को हटाने, घाटों के सौंदर्यीकरण, और तटीय हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबन्ध लागू किया जाएगा, क्योंकि सीवर सिस्टम को चोक करने और प्रदूषण बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अन्तर्गत इसी वर्ष जनवरी में गठित गोमती टास्क फोर्स में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम, लखनऊ नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गोमती का जल जीवन का आधार है, और इसे स्वच्छ, अविरल तथा निर्मल बनाए रखना उत्तर प्रदेश की नैतिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। टास्क फोर्स की मासिक बैठक नियमित रुप से आयोजित की जाएं। त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए और प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता व जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब समाज और शासन साथ कदम बढ़ाएँगे, तभी गोमती अपनी स्वाभाविक निर्मलता और जीवनदायिनी धारा पुनः प्राप्त कर सकेगी।

विंध्य और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हर घर में 15 दिसम्बर, 2025 तक नल से शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 13 अक्टूबर, 2025 को यहां लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में 'जल जीवन मिशन-हर घर नल योजना' की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।मुख्यमंत्री जी ने बैठक में विंध्य और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हर घर में नल से शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर, 2025 की समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा है कि इस अवधि तक न केवल नल कनेक्शन लगाए जाने हैं, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिट भी करा ली जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह योजना केवल पेयजल आपूर्ति का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन-स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता से सीधा जुड़ा मिशन है। योजनाओं की समय-सीमा और गुणवत्ता, दोनों पर कोई भी समझौता स्वीकार नहीं होगा। कहीं भी किसी भी स्तर पर धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री जी ने एन0सी0सी0 लिमिटेड, लार्सन एण्ड टुब्रो, मेघा इंजीनियरिंग, पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक, आई0सी0 इन्फ्रा, पावर मैक, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स सहित अनेक एजेंसियों के प्रतिनिधियों से फील्ड में काम करने के दौरान आ रही चुनौतियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता, फेजवार अवशेष कार्य, बकाया और भुगतान सहित एजेंसियों के प्रतिनिधियों से हर आवश्यक विषय पर चर्चा की और कार्यों की गुणवत्ता व समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि दिसम्बर, 2028 तक बढ़ाने और परियोजना लागत में वृद्धि करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से कार्यों को निरन्तर जारी रखेगी, ताकि जनता को योजनाओं का लाभ समय से मिल सके।

बैठक में बताया गया कि केन्द्र सरकार के नामित नोडल अधिकारियों ने देश के 74 जनपदों में 147 योजनाओं का निरीक्षण किया, जिनमें से 132 योजनाएं संतोषजनक पायी गयीं। शिकायत निवारण प्रणाली के तहत राज्य द्वारा विकसित पोर्टल https://jalsamadhan.in को 13.5 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। पोर्टल पर 62,688 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 46,354 का निस्तारण हो चुका है। साथ ही टोल फ्री नम्बर 1800-121-2164 के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का संतुष्टि परक निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

प्रतिस्पर्धा ही विकास को प्रोत्साहित करती है, खेलकूद प्रतियोगिताएं इसमें सहयोगी बनती हैं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 13 अक्टूबर, 2025 को लखनऊ में आयोजित समारोह में लगभग 16 हजार मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 16 हजार से अधिक युवक एवं महिला मंगल दलों को उपलब्ध करायी जा रही स्पोर्ट्स किट उन्हें दीपावली के पूर्व एक उपहार है। आज ही सांसद एवं विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं का औपचारिक शुभारम्भ किया गया है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन का परिणाम है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खेल व्यक्ति को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से ही व्यक्ति व समाज विकास कर सकता है। लोगों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया, फिट इण्डिया मूवमेन्ट तथा सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं की शुरुआत की। अब विधायक खेलकूद प्रतियोगिताएं इनके साथ जुड़ गई हैं। इसके अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। अनेक नौजवानों को उनके जनपद में खेलने का एक मंच मिला है और लोगों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जाग्रत हुई है। यह प्रतिस्पर्धा ही विकास को प्रोत्साहित करती है। खेलकूद प्रतियोगिताएं और स्पोर्ट्स किट इसमें सहयोगी बनते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 01 लाख 05 हजार से अधिक युवक एवं महिला मंगल दल सक्रिय हैं। इनका दायित्व है कि अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों से खेलकूद की प्रतिस्पर्धाओं का शुभारम्भ करें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खेल में टीम भावना का होना भी अत्यन्त आवश्यक है। टीम भावना से कैसे सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि युवक एवं महिला मंगल दलों का काम सरकार से केवल स्पोर्ट्स किट प्राप्त करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। खेलकूद के साथ-साथ हमारे गांवों में लोक कथाओं, लोक गायन तथा लोक परम्पराओं का आयोजन भी होना चाहिए। इनमें हमारा इतिहास, परम्पराएं और पूर्वजों की गाथाएं छुपी होती हैं। इस प्रकार के आयोजन अपने पूर्वजों की गाथाओं को पुनर्जीवित करने और उसे मंच देने का माध्यम हो सकते हैं। गांवों में इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन प्रारम्भ होने चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोनभद्र के भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि खेलकूद की स्पर्धा के साथ ही बुजुर्गों के बीच रस्सा-कसी का आयोजन भी किया गया था। इसमें लोगों ने उत्साह से भाग लिया था। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग प्रतियोगिताएं, गायन तथा नाटक मंचन आदि भी हो रहे थे। यह सभी कला की अलग-अलग विधाएं हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का विजन खेल के साथ-साथ अन्य अलग-अलग विधाओं के माध्यम से भी आगे बढ़ रहा है। युवक एवं महिला मंगल दलों को भी इस अभियान का हिस्सा बनते हुए यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा, स्वावलम्बन व सशक्तिकरण के उद्देश्य से मिशन शक्ति का 5वां चरण संचालित कर रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनके कल्याण के लिए संचालित केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उन्हें देना है। महिला मंगल दलों का यह दायित्व है कि अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम से जुड़ें और उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं।

इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय युवा उत्सव-2025 और यूथ पार्लियामेंट-2025 के विजेता प्रतिभागियों का सम्मान किया। उन्होंने सांसद-विधायक खेल स्पर्धा एवं विकासखण्ड स्तर पर संचालित युवा संवर्धन केन्द्रों का शुभारम्भ किया।

सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से वंचित न रहे: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 13 अक्टूबर, 2025 को यहां लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी मण्डल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से वंचित न रहे। प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर अत्याधुनिक पुनर्वास केन्द्र विकसित किए जाएं, जहां दिव्यांग व्यक्तियों को चिकित्सकीय, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक सहायता एक ही स्थान पर मिल सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार 'सेवा, संवेदना और सम्मान' के भाव से दिव्यांगजनों के समग्र सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि दिव्यांगजन केवल सहानुभूति के पात्र बनकर न रहें, बल्कि आत्मनिर्भर और योगदानकारी नागरिक के रूप में समाज की मुख्यधारा में शामिल हों।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि जिन जनपदों में पहले से दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालित हैं, उनकी सेवाओं को और सशक्त करते हुए मॉडल केंद्रों के रूप में विकसित किए जाएं। जहां केन्द्र नहीं हैं, वहां उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय जिला या सरकारी अस्पतालों के परिसर में स्थापित किया जाए ताकि चिकित्सकीय सुविधाओं के साथ इनका सहज समन्वय बन सके। यदि सरकारी अस्पताल में स्थान पर्याप्त नहीं है तो अलग भवन की व्यवस्था की जाए। इन केन्द्रों में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, ऑर्थोटिक व प्रॉस्थेटिक सेवाएं, उपकरण वितरण आदि सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हों।

बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश के 37 जनपदों में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कार्यरत हैं, इनमें 11 मण्डल मुख्यालयों पर हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन केंद्रों में तकनीकी संसाधन और विशेषज्ञ मानवबल को सुदृढ़ किया जाए। प्रत्येक केंद्र में प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट, ऑर्थोटिस्ट, स्पीच थैरेपिस्ट और काउंसलर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल पंजीकरण, और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाए ताकि सेवाओं की पारदर्शिता और निगरानी बनी रहे।

प्रदेश के नगरों के तीव्र गति से बदलते विकास स्वरूप को देखते हुए अब एक व्यापक 'शहरी पुनर्विकास नीति' की आवश्यकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 14 अक्टूबर, 2025 को यहां लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में आवास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के नगरों के तीव्र गति से बदलते विकास स्वरूप को देखते हुए अब एक व्यापक 'शहरी पुनर्विकास नीति' की आवश्यकता है। यह नीति केवल भवनों के पुनर्निर्माण तक सीमित न रहकर शहरों के समग्र पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारे नगर केवल इमारतों का समूह नहीं, बल्कि जीवंत सामाजिक संरचनाएँ हैं। इनके पुनर्जीवन के लिए ऐसी नीति आवश्यक है, जो आधुनिकता, परंपरा और मानवता तीनों का संतुलित समन्वय करे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य पुराने, जर्जर और अनुपयोगी क्षेत्रों को आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे, पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाओं और पर्यावरणीय संतुलन के साथ विकसित करना है। नीति में ऐसे प्राविधान किए जाएं, जिनसे निवास योग्य, सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित नगरों का निर्माण सुनिश्चित हो।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि नीति में भूमि पुनर्गठन, निजी निवेश को प्रोत्साहन, पारदर्शी पुनर्वास व्यवस्था और प्रभावित परिवारों की आजीविका की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। हर परियोजना में 'जनहित सर्वोपरि' की भावना हो तथा किसी की सम्पत्ति या जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके लिए न्यायसंगत और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नई नीति में राज्य स्तरीय पुनर्विकास प्राधिकरण, परियोजनाओं की सिंगल विंडो अप्रूवल प्रणाली तथा पी0पी0पी0 मॉडल को प्राथमिकता दी जाए। निवेशकों को स्पष्ट दिशा-निर्देश, प्रोत्साहन और सुरक्षा दी जाए, ताकि निजी क्षेत्र पुनर्विकास में सक्रिय भागीदारी कर सके। साथ ही, हर परियोजना में हरित भवन मानक, ऊर्जा दक्षता और सतत विकास के प्राविधान अनिवार्य किए जाएं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नगरों की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। पुराने बाजारों, सरकारी आवास परिसरों, औद्योगिक क्षेत्रों और अनधिकृत बस्तियों के लिए क्षेत्रवार अलग रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने नीति में सेवानिवृत्त सरकारी आवासों, पुरानी हाउसिंग सोसायटियों तथा अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई नीति का मसौदा जनप्रतिनिधियों, नगर निकायों और आम नागरिकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अन्तिम रुप से तैयार किया जाए और शीघ्र मंत्रिपरिषद के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए।

बैठक में नगरीय क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों द्वारा लिए जाने वाले बाह्य विकास शुल्क पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जी ने बाह्य विकास शुल्क को व्यावहारिक और जनहित के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सभी प्रकार के भूमि उपयोग आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और कृषि पर समान शुल्क दरें लागू हैं, जो व्यावहारिक नहीं हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि नई व्यवस्था में स्थान और भूमि उपयोग के आधार पर शुल्क दरों में अन्तर रखा जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि कृषि एवं औद्योगिक उपयोग की भूमि पर वाह्य विकास शुल्क, आवासीय और व्यावसायिक उपयोग की तुलना में कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर निकाय सीमा के भीतर और नगर निकाय सीमा के बाहर की भूमि पर भी शुल्क की दरों में अन्तर किया जाए, ताकि निवेशकों और आम नागरिकों दोनों के हितों का संतुलन बना रहे।

मुख्यमंत्री जी ने वाह्य विकास शुल्क की गणना प्रणाली में पारदर्शिता और सरलता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सामान्य व्यक्ति भी बिना किसी परेशानी के स्वयं अपने शुल्क की गणना कर सके। इसके लिए शुल्क निर्धारण का फॉर्मूला स्पष्ट, ऑनलाइन और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप वाला होना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वाह्य विकास शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग वास्तव में वाह्य बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, विद्युत व अन्य जनसुविधाओं के विकास में किया जाए। इसके लिए विकास प्राधिकरणों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आवास विभाग को निर्देश दिया कि वाह्य विकास शुल्क से संबंधित वर्तमान प्राविधानों की समीक्षा कर, जन सुलभ, पारदर्शी और व्यवहारिक नीति का प्रारूप शीघ्र तैयार किया जाए, ताकि नगरीय विकास योजनाओं में गति आए और नागरिकों को वास्तविक लाभ मिले।

कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 14 अक्टूबर, 2025 को यहां लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रुरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट (यूपी एग्रीज) के कार्यों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और डिजिटल रुप से सशक्त बनाना शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में 'डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम' के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बाजार, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सेवाओं से सम्बन्धित सभी सूचनाएं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम उपलब्ध हो सकें। इसके लिए प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति तैयार की जाए, जो राष्ट्रीय तकनीकी मानकों पर आधारित हो और सुरक्षित साइबर अवसंरचना तथा नवाचार आधारित अनुसंधान को प्रोत्साहित करे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 'बीज से लेकर बाजार तक' की प्रक्रिया को समग्र दृष्टिकोण से जोड़ते हुए यह परियोजना किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने और राज्य के कृषि क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत एवं डिजिटल टिकाऊ कृषि तंत्र को आगे बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 'कृषि से उद्योग तक' की सोच के साथ कार्य करते हुए मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश विविध कृषि सहायता परियोजना (यूपीडास्प) के समन्वयन में यूपी एग्रीज का क्रियान्वयन करते हुए कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान उत्पादक संगठनों को भी परियोजना से जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना के प्रत्येक घटक के परिणामों की नियमित समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंचे। यूपी एग्रीज के कार्यों की सतत मॉनिटरिंग के आवश्यक प्रबन्ध किये जाएं। उन्होंने परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सेक्टोरल विशेषज्ञों की नियुक्ति पर भी जोर दिया।उन्होंने कहा कि उन्नतशील बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियोजित प्रयास किए जाएं।

मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि कमोडिटी क्लस्टर दृष्टिकोण के तहत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में मूंगफली, वाराणसी में लाल मिर्च व सब्जी, बाराबंकी से आज़मगढ़ तक केला और अन्य जनपदों में काला नमक चावल, हरी मटर, उड़द, आलू आदि के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'टिशू कल्चर' को प्रोत्साहित किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने मत्स्य क्षेत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि मछली के सीड प्रदेश में ही तैयार किए जाएं, इससे मत्स्यपालकों की लागत घटेगी। उन्हें बताया गया कि क्लस्टर विकास के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्तापूर्ण बीज आपूर्ति, नवीन तकनीक के प्रयोग और उत्पादन से विपणन तक के प्रबंधन सुधार की ठोस व्यवस्था की जा रही है। परियोजना के अंतर्गत लगभग 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य उत्पादन के लिए विकसित करने का लक्ष्य है, जिससे लगभग एक लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृषि वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों तथा कृषि आधारित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण सुविधा, जोखिम प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था और निजी निवेश के प्रोत्साहन पर बल दिया जाए।

प्रदेश के 1.86 करोड़ पात्र परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल सब्सिडी हस्तान्तरित की : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 अक्टूबर, 2025 को यहां लखनऊ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रदेश के 1.86 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल वितरण के शुभारम्भ कार्यक्रम में 10 लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किये।

इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में तय किया था कि वर्ष में 02 बार, होली व दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराए जाएंगे। आज यहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पात्र लाभार्थियों को 1,500 करोड़ रुपये की धनराशि से निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया जा रहा है। यह दीपावली पर्व का उपहार है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रसोई गैस नारी गरिमा व स्वच्छ पर्यावरण का प्रतीक बन चुकी है। निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर प्राप्त होने से हुई बचत को परिवार के अन्य खर्चों में उपयोग किया जा सकता है। लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व जरूरतमंदों को शासन की योजनाओं का लाभ पूरी निष्ठा के साथ उपलब्ध कराना होता है। अच्छी सरकार लोकमंगल की कामना के साथ सभी नागरिकों के हित के विषय में सोचती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सबका साथ सबका विकास' मंत्र के माध्यम से सभी जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। देश में 11 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराए गए। प्रदेश में 01 करोड़ 86 लाख परिवारों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए प्रदेश में कानून-व्यवस्था का बेहतर वातावरण निर्मित किया गया है। इस वातावरण में बेटियां तथा व्यापारी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विगत साढ़े आठ वर्षों में सभी समुदायों के त्योहार जैसे होली, दीपावली, विजयदशमी, जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किये गये हैं। पर्व व त्योहार अपनी-अपनी आस्था के अनुरूप सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का एक माध्यम होते हैं। इनका उद्देश्य सामूहिक रूप से परिवार की खुशियों को समाज, प्रदेश व देश के साथ आपस में बांटना है।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि दीपावली त्योहार के अवसर पर स्थानीय हस्तशिल्पियों व कारीगरों द्वारा बनाये गये दीप, लक्ष्मी-गणेश जी की प्रतिमा व अन्य स्वदेशी सामग्रियों को खरीदें। स्वजनों, शुभचिन्तकों तथा मित्रों को उपहारस्वरूप स्वदेशी वस्तुएं भेंट करें। इससे हस्तशिल्पियों व कारीगरों के उद्यम को बल मिलेगा। स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री से होने वाला मुनाफा श्रमिकों, हस्तशिल्पियों व कारीगरों को मिलेगा। इससे वे समृद्ध होंगे तथा यही समृद्धि देश के काम आएगी। इससे विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी।